जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

अजमेर

Rashtradoot

फोनः- 2627612, 2427249 फैक्सः- 0145-2624665 वर्षः 36 संख्याः 254 प्रभात अजमेर, गुरूवार 23 अप्रैल, 2026 आर.जे./ए.जे./73/2015-2017 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

अजीब सा लगा, जब गहलोत व पायलट एक ही मंच पर, गले मिलते, हँसते, गल-बहियां होते नज़र आए

मौका था, कांग्रेस ओबीसी काउंसिल की बैठक का, जो राहुल गांधी ने आहूत की थी

- राहुल गांधी का मैसेज था कि देश के व राज्यों के ओबीसी नेता मिलकर बैठें तथा ओबीसी के मुद्दों पर एक सर्वमान्य राय बनाएं, जिससे यह उभर कर सामने आए कि ओबीसी के कौन से मुद्दे, राष्ट्रीय स्तर पर उठाए जा सकते हैं।
- राहुल ने इसी संदर्भ में आगे कहा कि अब तक उनके पास नेता अपनी व्यक्तिगत परेशानियाँ लेकर आते थे, यह रूकना चाहिए तथा इन नेताओं को तय करना चाहिए, मिल बैठकर, कि कौन से मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर उठाने चाहिए, किन मुद्दों को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- शायद राहुल की इस सोच की अनुपालना में गहलोत और पायलट के प्रेम पूर्वक मिलाप का अद्भुत दृश्य देखने को मिला।

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 अप्रैल। राजस्थान कांग्रेस के दो ओबीसी नेता, जो आमतौर पर एक-दूसरे के कट्टर विरोधी माने जाते हैं और एक-दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, हाल ही में हाथ मिलाते, साथ में हँसते और परस्पर समर्थन, प्रेम तथा एकता का संदेश देते हुए देखे गए।

वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने तस्वीरें खींच रहे फोटोग्राफरों से कहा कि वे इन तस्वीरों को क्लिक करें और सुरक्षित रखें।

दूसरे नेता सचिन पायलट थे।

दोनों इंदिरा भवन में राहुल गांधी द्वारा बुलाई गई कांग्रेस ओबीसी परिषद की बैठक में उपस्थित थे।

दिलचस्प बात यह रही कि राहुल गांधी ने चर्चा की शुरुआत विभिन्न राज्यों और देशभर से आए ओबीसी नेताओं से यह कहकर की कि वे एकजुट हों, साथ आएं, महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनाएं, जिन मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की जरूरत है उन्हें तय करें, और फिर सहमति वाले मुद्दों के साथ उनके पास आएं, ताकि वे उन्हें पार्टी के भीतर और अन्य मंचों पर उठा सकें। राहुल गांधी ने कहा कि नेता उनके पास व्यक्तिगत रूप से अपने-अपने मुद्दों के साथ आते हैं, लेकिन अब यह बंद होना चाहिए और उन्हें उन अहम मुद्दों को प्राथमिकता देनी चाहिए, जिन पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है।

राहुल गांधी ने उपस्थित ओबीसी नेताओं से यह भी कहा कि सरकार उनकी जातिगत जनगणना की मांग मान चुकी है, और यह कार्य यह सुनिश्चित करने के लिए होना ही चाहिए कि ओबीसी, दलित और अन्य वर्गों को सत्ता संरचना में उनका उचित हिस्सा मिल सके, जिसकी वे मांग कर रहे हैं।

आईआरएस अफसर की बेटी की रेप के बाद हत्या

नई दिल्ली, 22 अप्रैल। दिल्ली के कैलाश हिल्स इलाके में बुधवार सुबह एक सीनियर आईआरएस अफसर के घर में उनकी 22 साल की बेटी की रेप के बाद हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार, घटना सुबह करीब 6 बजे हुई। युवती घर में अकेली थी।

आईआरएस अफसर और उनकी पत्नी रोज की तरह जिम गए हुए थे। वापस लौटे तो बेटी का शव कमरे में मिला। वह यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। शुरुआती जांच के अनुसार,

- पुलिस ने आरोपी राहुल मीणा को एक होटल से गिरफ्तार कर लिया है। वह उक्त अफसर के घर में नौकर था।

उसके साथ पहले रेप किया गया। फिर मोबाइल चार्जर के तार से गला घोंटकर हत्या की गई।

घटना के करीब 14 घंटे बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी, 19 साल के राहुल मीणा को गिरफ्तार किया। वह द्वारका इलाके के एक होटल में छिपा हुआ था। वह आईआरएस अफसर के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या ममता बनर्जी बौखला गई हैं चुनाव की टैंशन के कारण

एक के बाद एक इतनी अजीबोगरीब टिप्पणियाँ कर रही हैं, अब जनता ने इन पर ध्यान देना ही बंद कर दिया है

- उदाहरण के लिए, उन्होंने कहा, जलियाँवाला काण्ड के बाद, इस खौफनाक लोमहर्षक घटना के बारे में महात्मा गांधी ने एक भावभीनी कविता लिखी थी, पर यह सर्वविदित है, जिस कविता का ममता जी उल्लेख कर रही हैं, रविन्द्र नाथ टैगोर ने लिखी थी, नोबल पुरुस्कार मिलने के बाद।
- यहाँ तक कि जब ममता जी ने ईडी के छापे के दौरान, घटना स्थल पर पहुँचकर, ईडी द्वारा जब्त कागज़ात व फाइलें, अपने पुलिस के जत्थे की मदद से जोर जबरदस्ती से उठा लाई थी तो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जब यह मामला पहुँचा ममता जी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बड़े-बड़े वकील पैरवी कर रहे थे।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 अप्रैल। राज्य विधानसभा चुनावों की पूर्व संध्या पर, राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से एक और कड़ी फटकार मिली।

सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी के व्यवहार पर बेहद कड़ी टिप्पणी की। शीर्ष अदालत ने राज्य की मुख्यमंत्री को उस स्थान पर जाने के लिए फटकार लगाई, जहां ईडी कोयला चोरी और विदेशी मुद्रा उल्लंघन की जांच के सिलसिले में तलाशी और जब्ती की कार्रवाई कर रहा था।

बताया गया कि मुख्यमंत्री जबरन वहां पहुंचीं और ईडी द्वारा जब्त किए गए दस्तावेज अपने साथ ले गईं। वे राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ ईडी की कार्रवाई के बीच पहुंचीं और एजेंसी की आलोचना करते हुए आधिकारिक फाइलें लेकर वहां से चली गईं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार का व्यवहार भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में अभूतपूर्व है और यह न्याय, निष्पक्षता तथा कार्यपालिका की संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प.बंगाल की 84 एससी/एसटी बहुल सीटें तय करेगी, किसकी सरकार बनेगी

ये सीटें जंगल महल बैल्ट, उत्तरी बंगाल और दक्षिण बंगाल की मातुआ बैल्ट में फैली हैं

- वर्ष 2006 तक इस क्षेत्र में वाम मोर्चा का दबदबा था तब इसने यहाँ कि 84 सीटों में से 72 सीटें जीती थीं, पर, 2011 में ममता बनर्जी ने वाम मोर्चा से यह गढ़ छीन लिया। 2016 में भी ममता बनर्जी ने 84 में से 66 सीटें जीती थीं।
- लेकिन 2021 के गत विधानसभा चुनावों में भाजपा ने इस क्षेत्र में दबदबा बढ़ाया और 84 में से 39 सीटें जीतीं और तृणमूल (36 सीटें) से बराबरी पर रही। इस बार भाजपा व तृणमूल दोनों पूरा जोर लगा रही हैं कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतें।

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 अप्रैल। चूँकि बंगाल में गुरुवार को पहले चरण का मतदान शुरू होता है, इसलिये सभी की नजरें जंगलमहल क्षेत्र, उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल की 'मातुआ बेल्ट' (जिसमें नदिया और उत्तर 24 परगना जैसे जिले शामिल हैं) में फैली 84 अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) सीटों के मतदान रुझानों पर टिकी हैं।

इन सीटों पर जो भी पार्टी बढ़त हासिल करेगी, उसके सरकार बनाने की संभावना अधिक होगी। इन क्षेत्रों में चुनावी मुकाबले को और महत्वपूर्ण बनाने वाली बात यह है कि पिछले कुछ चुनावों में मतदाताओं की बदलती निष्ठाएं साफ तौर पर दिखाई दी हैं। ये सीटें, जो कभी वाम मोर्चा का अभेद्य गढ़ मानी जाती थीं, अब बंगाल की राजनीति का सर्वाधिक अप्रत्याशित रणक्षेत्र बन गई हैं। 2006 में वाम मोर्चा ने इन 84 में से 72 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 2011 के चुनावों में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस की परिवर्तन लहर के बीच उसका पूरी तरह सफाया हो गया। इसके बाद 2016 के चुनावों में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने 84 में से 66 सीटें (50 एससी और 16 एसटी) जीतीं। लेकिन 2021 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय पैठ बनाई, तथा उसने 32

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चुनाव आयोग ने खड़गे को नोटिस दिया

नई दिल्ली, 22 अप्रैल। चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को कथित तौर पर 'आतंकवादी' कहे जाने के विषय को गंभीरता से लेते हुए उन्हें नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे के भीतर जवाब तलब किया है।

चुनाव आयोग के अधिकारी सूत्रों ने आज इसकी जानकारी दी। तमिलनाडु

- खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री को 'आतंकवादी' कहने को आयोग ने गंभीरता से लिया।

में संवाददाता सम्मेलन में खड़गे ने प्रधानमंत्री को कथित तौर पर 'आतंकवादी' कहा था। भारतीय जनता पार्टी ने मामले को गंभीर बताते हुए कांग्रेस अध्यक्ष की प्रधानमंत्री पर की गई टिप्पणी की तीखी आलोचना की थी। इस मुद्दे पर भाजपा का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के नेतृत्व में आज चुनाव आयोग से मिला था। दूसरी ओर, कांग्रेस अध्यक्ष ने इस पर सफाई देते हुए कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री को आतंकवादी नहीं कहा, बल्कि उनका अर्थ था कि वे राजनेताओं को डरा रहे हैं।

बंगाल चुनाव में मोटरसाइकिल चलाने पर लगा प्रतिबंध

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए जो ''अभूतपूर्व'' प्रतिबंध लगाए हैं, उनमें बाइक पर प्रतिबंध को ''सबसे ज्यादा अभूतपूर्व'' माना जा रहा है।

- आयोग ने मतदान के दो दिन पहले से मतदान के अगले दिन तक के लिए बाइक चलाने और पीछे सवारी बिठाने पर रोक लगाई है, केवल आपात स्थिति में ही इसमें छूट दी जा सकती है पर इसके लिए पुलिस थाने में सूचित कर अनुमति लेनी होगी।
- आयोग के इस फैसले की भारी आलोचना हो रही है, खासकर गिग वर्कर्स और रैपिडो आदि में बाइक चलाने वालों की तरफ से। उनका कहना है इससे उनके लिए रोजी-रोटी का संकट पैदा हो जाएगा।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 अप्रैल। पश्चिम बंगाल में होने वाले दो चरणों के चुनाव के मद्देनज़र मोटरसाइकिलों के उपयोग पर एक अभूतपूर्व प्रतिबंध लगाया गया है। चुनाव आयोग ने मतदान से 48 घंटे पहले मोटरसाइकल के इस्तेमाल पर रोक लगा दी, यहां 23 अप्रैल को मतदान है। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक वही, मोटर साइकिल चला सकेंगे, जिन्हें अति आवश्यक काम है। आवाजाही प्रतिबन्धित कर दी है, सिवाय ''आपातकालीन'' और पारिवारिक जरूरतों के। साथ ही, मोटरसाइकिल रैलियों पर पूरी तरह रोक लगाई गई है।

आयोग के बयान में कहा गया है, ''मतदान दिवस से दूसरे दिन तक सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक मोटरसाइकिल पर पीछे बैठकर (पिलियन राइडिंग) यात्रा की अनुमति नहीं होगी, सिवाय चिकित्सा आपातकाल, पारिवारिक कार्यक्रम या अन्य आवश्यक जरूरतों, जैसे बच्चों को स्कूल छोड़ने/लेने के मामलों के।

बयान में यह भी कहा गया, ''परिवार के साथ पिलियन राइडिंग की सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान के उद्देश्य से और अन्य आवश्यक जरूरतों, जैसे चिकित्सा आपातकाल, पारिवारिक कार्यक्रम आदि के लिए अनुमति दी जाएगी।'' चुनाव आयोग ने कहा कि किसी भी प्रकार की छूट के लिए लोग पहले से स्थानीय पुलिस के पास आवेदन कर सकते हैं।

बाद में आयोग ने स्पष्ट किया कि उचित पहचान पत्र सहित दफ्तर जाने वाले लोगों को भी छूट दी जाएगी।

आयोग ने कहा कि उसका उद्देश्य ''स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और हिंसा-मुक्त चुनाव सुनिश्चित करना'' है। इसी दिशा में, आयोग ने राज्य में शराब बिक्री पर प्रतिबंध की अवधि को पहले ही दोगुना दिया था। सामान्य 48 घंटे का प्रतिबंध बढ़ाकर 96 घंटे कर दिया गया, जो रविवार से लागू हुआ।

19 अप्रैल के एक बयान में चुनाव आयोग ने कहा था, यह देखा गया है कि शराब की बिक्री में असामान्य वृद्धि हुई है। यह निष्कर्ष विभिन्न स्रोतों, जिनमें शराब निगरानी अभियान भी शामिल हैं, के आधार पर निकाला गया। आयोग के अनुसार, अप्रैल में शराब की बिक्री पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में अधिक रही है।

पश्चिम बंगाल में यह हाई-स्टेक विधानसभा चुनाव 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में होंगे, जबकि मतगणना 4 मई को होगी।

लिपुलेख दर्रा से भारत-चीन व्यापार जून में शुरु होगा

पिथौरागढ़, 22 अप्रैल। लिपुलेख दर्रा के माध्यम से भारत-चीन सीमा व्यापार वर्ष 2026 के जून के प्रथम सप्ताह से शुरू होकर सितंबर तक चलेगा। भारत-चीन सीमा व्यापार को वर्ष 2026 में पुनः शुरू करने की तैयारियों को लेकर

- करीब 6 साल के बाद यहां से व्यापार शुरु करने की विदेश मंत्रालय ने स्वीकृति दी।

बुधवार को जिलाधिकारी आशीष भटगांई की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। विदेश मंत्रालय से लिपुलेख दर्रे के माध्यम से व्यापार शुरू करने की अनापत्ति मिलने के बाद प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है।

करीब छह वर्षों के अंतराल के बाद फिर से शुरू हो रहे इस सीमा व्यापार को लेकर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है और सभी व्यवस्थाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

ट्रंप ने ईरान के साथ अनिश्चितकाल तक सीज़फायर बढ़ाने का श्रेय पाकिस्तान को दिया

अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर साफ-साफ लिख पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर और पाक प्र.मंत्री शहबाज़ शरीफ के अनुरोध पर वे अनिश्चितकाल के लिए सीज़फायर बढ़ा रहे हैं

- ट्रंप ने कहा कि ईरान की सरकार में भारी विभाजन है और जब तक उनकी तरफ से सर्व सम्मत संधि प्रस्ताव नहीं आ जाता, अमेरिकी सेना ईरान पर हमला नहीं करेगी, लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में अमेरिका की नाकेबंदी जारी रहेगी।
- विशेषज्ञों का कहना है कि पहले ईरान के नेताओं ने शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान का आभार जताया था और अमेरिका भी पाकिस्तान को श्रेय दे रहा है, इससे अंतर्राष्ट्रीय जगत में पाकिस्तान की कूटनीतिक ताकत बढ़ेगी।
- उग्रवाद और कमज़ोर अर्थव्यवस्था के कारण दुनिया भर में समस्याग्रस्त राष्ट्र के रूप में देखा जाने वाला देश पाकिस्तान अब अचानक सुर्खियों में आ गया है। पर, मध्यस्थ की यह भूमिका कांटों का ताज है। अगर शांति वार्ता विफल रही तो इसका प्रभाव पाकिस्तान को भी झेलना होगा।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 अप्रैल। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने अमेरिका-ईरान युद्धविराम समाप्त होने से कुछ घंटे पहले ही इसे अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया, और इसके लिए पाकिस्तान के निवेदन का हवाला दिया। अपने बयान में ट्रंप ने कहा कि वे गंभीर रूप से विभाजित ईरानी शासन को स्थायी शांति समझौते के लिए एकीकृत प्रस्ताव तैयार करने का समय देना चाहते हैं। यह पहली बार है, जब अमेरिका ने तेहरान की अगली कार्रवाई के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की है, और ट्रंप ने अपनी रणनीति में बदलाव का श्रेय पाकिस्तानी नेतृत्व के साथ हुई बातचीत को दिया है।

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर लिखा, इस तथ्य के आधार पर कि ईरान की सरकार गंभीर रूप से विभाजित है, जो अप्रत्याशित नहीं है, और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तथा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अनुरोध पर, हमने ईरान पर अपने हमले तब तक रोकने के लिए कहा है, जब तक उनके नेता और प्रतिनिधि कोई एकीकृत प्रस्ताव लेकर नहीं आते।''

लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में ईरान के तट पर बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रहेगी, ट्रंप ने कहा, जबकि अमेरिकी सेना ''अन्य सभी मामलों में तैयार और सक्षम'' रहेगी।

उन्होंने कहा कि युद्धविराम ''तब तक बढ़ाया जाएगा, जब तक उनका प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हो जाता और उस पर चर्चा पूरी नहीं हो जाती, किसी भी तरह से।''

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बाद में युद्धविराम बढ़ाने के अनुरोध को स्वीकार करने और उसके ''कूटनीतिक प्रयासों'' पर ''विश्वास और भरोसा'' दिखाने के लिए ट्रंप का धन्यवाद किया।

उन्होंने एक्स पर लिखा, मेरी ओर से और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ओर से, मैं राष्ट्रपति ट्रंप का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए युद्धविराम बढ़ाया, ताकि चल रहे कूटनीतिक प्रयास आगे बढ़ सकें। पाकिस्तान इस विश्वास और भरोसे के साथ अपने प्रयास जारी रखेगा बातचीत के जरिए समाधान निकाला जा सके।''

उन्होंने आगे कहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों पक्ष युद्धविराम का पालन करेंगे और इस्लामाबाद में निर्धारित दूसरे दौर की वार्ता के दौरान एक व्यापक ''शांति समझौते'' पर पहुंच सकेंगे, जिससे संघर्ष का स्थायी अंत हो सके।

यदि इस्लामाबाद वास्तव में ट्रंप को ईरान पर आगे के हमलों को रोकने के लिए प्रभावित कर पाया है, तो इससे उसकी कूटनीतिक स्थिति को बड़ा बढ़ावा मिलेगा और वैश्विक स्तर पर उसकी साख मजबूत होगी।

इससे पहले, ईरानी नेताओं ने भी कई मौकों पर पाकिस्तान के कूटनीतिक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया था।

ईरान और अमेरिका के बीच मतभेदों को कम करने के लिए पाकिस्तान के तेज प्रयासों के पीछे

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

संजय झा फिर जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने

पटना, 22 अप्रैल। बिहार की प्रमुख राजनीतिक पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जदयू)) ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के नेतृत्व में संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव किए

- पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा सांसद आलोक कुमार सुमन को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया।

गए हैं। इस फेरबदल को आगामी चुनावों के मद्देनज़र महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

जदयू की नई टीम में संजय झा को एक बार फिर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, जहानाबाद के पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। गोपालगंज से सांसद आलोक कुमार सुमन को पार्टी का राष्ट्रीय

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)